राव इन्द्रजीत की खुली बगावत पटौदा रैली में खुल कर ललकारा केन्द्रीय नेतृत्व को

मजदूर मोर्चा ब्यूरो झज्जर

दो सप्ताह पूर्व मज़दूर मोर्चा ने केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत के तेवर भांपते हुए लिखा था कि वे राजनीति के कुशल खिलाड़ी होने के नाते मोदी-शाह के काबू आने वाले नहीं हैं। उन्होंने 23 तारीख को झज्जर के निकट पटौदा खेड़ा आयोजित रैली में खुल कर अपना आगामी प्रोग्राम घोषित कर दिया। शहीदी दिवस के नाम से आयोजित इस रैली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, चार विधायक व चार सांसद मंच पर मौजूद थे। केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की हरियाणा में घुसपैठ की ओर इशारा करते हुए उनहोंने कहा कि वे पैराशूट द्वारा उतारे गए राजनेता नहीं हैं, वे ज़मीन से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं।

केन्द्रीय नेतृत्व की 75 साल की आयु होने पर रिटायर कर देने वाली नीति को धता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल अहीरवाल पर ही लागू करना चाहते हैं। उनकी यह नीति यहां कतई चलने वाली नहीं है। वैसे तो उन्होंने आगामी चुनाव न लड़ने की सोच रखी थी परन्तु जिस तरह से उनको बेइज्जत करके हाशिये पर धकेलना चाहते हैं, इसमें वे सफ़ल नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को 'पानीपत' की लड़ाई लड़ने के लिये कमर कस लेने का आह्वान किया।

सांसद असदुद्दीन अवैसी के घर पर हमला: दंगे भड़काने का संघी प्रयास

नई दिल्ली (म.मो.) हिंदू सेना का लेबल लगाकर कुछ संघी गुंडों ने, अकबर रोड स्थित, हैदराबाद से चुने सांसद असदुद्दीन अवैसी के सरकारी घर पर हमला कर काफ़ी तोड़-फ़ोड़ कर डाली। गृहमंत्री अमितशाह की दिल्ली पुलिस ने थाना पूर्ति करते हुए पांच उपद्रवियों को हल्की-फ़ुल्की धाराओं में गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया।

इस तोड़-फ़ोड़ से सांसद अवैसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जो हुआ वह सरकारी इमारत का हुआ। जिसकी मुरम्मत पर सरकारी पैसा खर्च किया जायेगा। दरअसल इस हमले के पीछे संघ परिवार का असल मकसद अवैसी को नुक्सान पहुंचाना नहीं था। उनका असल मकसद मुसलमानों को भड़काने व जवाबी कार्यवाही करने के लिये उकसाना था। उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो संघ परिवार की प्रतिष्ठा के लिये अति महत्वपूर्ण है, को जीतने के लिये हिंदू-मुस्लिम दंगे कराना अति आवश्यक हो गया लगता है।

यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट द्वारा मुसलमानों के सैंकड़ों घर, अनेकों मस्जिदें गिराने व उन पर हर तरह के अत्याचार करने के बावजूद भी मुसलमान भड़क कर जवाबी कार्यवाही नहीं कर रहे। इससे बिष्ट एवं संघ परिवार अत्यधिक परेशान हैं। इसलिये ये लोग कभी हरियाणा के मेवात, कभी कर्नाटक में तो अब दिल्ली में इस तरह की भड़काने वाली कार्यवाही करने पर उतारू हैं। लेकिन लगता है कि मुसलमान संघियों की चाल को बखूबी समझते हुए शांत रहकर, चुनाव के मौके पर असल चोट करने की प्रतीक्षा में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दंगा कराने के लिये किसी बड़े हिंदू या मुस्लिम नेता की हत्या भी करा सकते हैं।

कांग्रेसी दफ़्तर पर भाजपाई प्रदर्शन: खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 18 सितम्बर को भाजपाईयों ने सेक्टर 11-12 की विभाजक सड़क पर स्थित कांग्रेसी कार्यालय पर एक धरने व प्रदर्शन का टुच्चा सा आयोजन किया। पूर्व सूचना के आधार पर कांग्रेसी भी पर्याप्त संख्या में, उनसे निपटने को, अपने दफ्तर में मौजूद थे। भाजपाईयों द्वारा तमाम तरह के भड़कावे के बावजूद वे भड़के नहीं। भड़कने के बजाय उन्होंने भाजपाईयों को गुलाब भेट करने के साथ-साथ चाय-नाश्ता आदि पेश किया। इससे अपमानित होकर भाजपाईयों ने नाश्ते पर ठोकर मारकर बिखेर दिया।

अपमान से झल्लाए भाजपाईयों ने उग्र रूप धारण करते हुए नारेबाज़ी शुरू कर दी। भाजपाई बोलते, 'भूपेन्द्र हुड्डा' तो जवाब में कांग्रसी बोलते, 'जिंदाबाद'। इसी तरह शैलजा व राहुल गांधी पर लगाए गए नारों का जवाब भी कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से दिया। संख्या बल में कांग्रेसी अधिक होने के चलते, नारेबाज़ी में कांग्रेसी भारी पड़े। इस पर बौखलाए भाजपाईयों ने कांग्रेसियों के साथ हाथापाई करने की जब कोशिश की तो उनकी रक्षा के लिये आई पुलिस ने बीच-बचाव करा कर उनको पिटने से बचा दिया।

भाजपाईयों का यह प्रदर्शन उस कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध था जिसके पल्ले आज न हरियाणा में कुछ है और न ही दिल्ली में। यह प्रदर्शन पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र के उस बयान को लेकर किया गया था जिसमें उन्होंने किसानों को पंजाब में आन्दोलन करने की बजाय केन्द्र सरकार के विरुद्ध दिल्ली में जाकर करना चाहिये। अब पंजाब में तो भाजपाईयों की, अपने बिलों से निकलने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि पंजाब के लोग उन्हें ढूंढ-ढूंढ कर व दौड़ा-दौड़ा कर ठोकते हैं। ऐसे में खिसियानी बिल्ली की तरह ये लोग हरियाणा में इस तरह की नौटंकी करते हैं।

आते-जाते लोगों ने भाजपाईयों पर टिप्पणियां करते हुए कहा कि जनता जिस महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा व नरक बने इस शहर को लेकर परेशान हैं उसके विरुद्ध क्यों नहीं आवाज उठाते? जिस अमरेन्द्र के बयान से इन्हें तकलीफ़ है तो उसका फ़रीदाबाद से क्या ताल्लुक है?

खोरी प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट में खट्टर सरकार की बार-बार फ़जीहत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते

फ़रीदाबाद (म.मो.) खोरी मामले को लेकर 20 सितम्बर को फरीदाबाद नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। इनके वाहियात जवाब व अक्रमण्यता को देख कर सर्वोच्च अदालत ने जम कर फ़टकार लगाते हुए अगले सप्ताह फ़िर से अवैध निर्माणों की पूरी लिस्ट और उन पर की गयी कार्यवाही का पूरा ब्योरा पेश करने को कहा। दरअसल नगर निगम के अधिकारी इतने हरामखोर व भ्रष्ट हो चुके हैं कि वे काम करने की बजाय टरकाने में ज्यादा भरोसा करते हैं अपनी इस गंदी आदत को वे सुप्रीम कोर्ट में भी त्यागने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इनके साथ अधिक सख्ती से पेश आना चाहिये। इसके लिये यदि 2-4 अफ़सरों को जेल भेज दिया जाये तो काम में बिजली जैसी फुर्ती आ जायेगी।

दूसरी समझने वाली बात यह है कि नगर निगम हो या 'हूडा', इनके अस्त्र-शस्त्र गरीबों पर पूरी तेज़ी से चलते हैं। खोरी इलाके में गरीबों के दसियों हज़ार घर उनके स्कूल व धार्मिक स्थल उजाड़ने में इन्हें कोई देर नहीं लगी, परन्तु सैंकड़ों फ़ार्म हाउसों, भव्य आश्रमों, शैक्षणिक भवनों व बड़े होटलों आदि की ओर इनकी झांकने तक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। इन्हें बचाये रखने के लिये तरह-तरह की नौटंकी व नये-नये तर्क खोजे जा रहे हैं। ड्रोन से सर्वे करा कर यह पता लगाया कि अवैध निर्माण कहां-कहां व कितने हैं; लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। वैसे काम करने की यदि नीयत हो तो ड्रोन सर्वे जैसी किसी नौटंकी की जरूरत नहीं है। सारे वन विभाग व नगर निगम को खूब अच्छे से पता है कि कहां क्या अवैध बना हुआ है।

अब एक तर्क गैर मुमकिन पहाड़ का भी उछाला जा रहा है। इसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि गैरमुमकिन पहाड़ जंगलात यानी वन क्षेत्र नहीं होता और पीएलपीए कानून के तहत संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। इसकी आड़ लेकर सरकार अपने लग्गुए-भग्गुओं की आलीशान इमारतों को बचाने का रास्ता खोज रही है। लेकिन हकीकत यह है कि सारा अरावली पहाड़ गैर मुमकिन में आता है सिवाय उन क्षेत्रों के जहां ग्रामीण खेती करते हैं और पटवारी-गिरदावर हर फ़सल का लेखा-जोखा जमाबंदी में चढाते हैं। इसके अलावा जंगलात विभाग के पास संरक्षित वन क्षेत्र के एक-एक इंच का लेखा-जोखा मौजूद है। इसके लिये न तो किसी ड्रोन सर्वे की आवश्यकता है और न ही मुमकिन या गैर मुमकिन की बहस में पड़ने की।

वास्तव में हुआ यह है कि समय-समय पर आई गयी राज्य सरकारों ने अपने चहेतों को संरक्षित क्षेत्र में घुसने व कब्जे करने के लिये मार्ग प्रशस्त किया। उनके सीएलयू किये व नक्शे आदि पास करके उन निर्माणों को

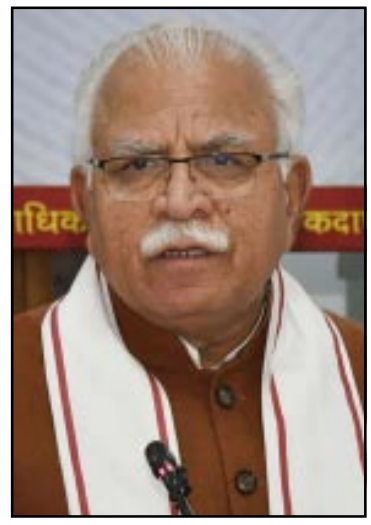

नियमित किया। कांत एन्क्लेव इसका बेहतरीन उदाहरण है। राज्य में समय-समय पर आये मुख्यमंत्रियों ने कांत एन्क्लेव को बसाया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमदी ने इसमें सहयोग दिया था। लेकिन इस सबके बावजूद गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस बनी-बनाई कॉलोनी को ध्वस्त करा दिया। उसी तर्क के आधार पर वन क्षेत्र, चाहे वह मुमकिन हो या गैरमुमकिन तमाम निर्माण जो वन क्षेत्र की परिधि में आते हैं ध्वस्त किये जा सकते हैं।

हर जगह गरीबों पर ही सरकार का हाथ चलता है

बाईपास चौड़ाने के नाम पर 20 किलोमीटर में हजारों पेड़ काट दिये, 10 शोरूम बचाने के लिये

फ़रीदाबाद (म.मो.) बाईपास को 12 लेन का हाईवे बनाने की मूल योजना के अनुसार इसे गुड़गांव नहर की ओर खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर बनना था। इसके लिये बसेलवा कॉलोनी, सेक्टर 18 व 17 के सामने पड़ने वाली झुग्गी बस्तियों को तुर्त-फुर्त साफ़ कर दिया गया। रास्ते में अटक रही खेड़ी पुल चौकी को भी वहां से हटा दिया गया। लेकिन मामला सेक्टर 9 के सामने आकर अटक गया। यहां 8-10 बड़े आलीशान शो रूम बने हुए हैं जो कि पूरी तरह से अवैध है, इनका कोई नक्शा पास नहीं है, ज़मीन भी नहर विभाग व 'हूडा' की है जिसका मुआवजा सरकार एक से अधिक बार दे चुकी है।

करोड़ों की लागत से बने ये शोरूम बचाने के लिये हाईवे की एलाइनमेंट ही बदल दी गयी। पहले जो एलाइनमेंट नहर के साथ से जानी थी अब उसे उक्त सेक्टरों के पीछे स्थित ग्रीन बेल्ट की ओर कर दिया गया। इस ग्रीन बेल्ट में हजारों बड़े पुराने व भारी पेड़ों के अलावा 'हूडा' द्वारा निर्मित रोज़ गार्डन भी था, जो सब तहस-नहस कर दिये गये।

कानूनी तौर पर ग्रीन बेल्ट पर उन सेक्टर वासियों का अधिकार है जिन्होंने 'हूडा' को पैसा देकर प्लॉट खरीदे हैं। विदित है कि प्लॉट की कीमत में सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट आदि के लिये छोड़ी गयी ज़मीन की कीमत भी शामिल होती है। यानी कि सड़कों व पार्कों आदि की तरह ग्रीन बेल्ट पर भी प्लॉट धारकों का कानूनी अधिकार होता है। इसके बावजूद सरकार ने ग्रीन बेल्ट व रोज गार्डन को सेक्टर वासियों से छीन लिया। जानकार बताते हैं कि उक्त शोरूम वालों ने स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर को जैसे-तैसे पटाया, इसके लिये मोटा लेन-देन होना स्वाभाविक है। सूत्र तो यहां तक भी दावा करते हैं कि तत्कालीन प्रशासक दहिया ने उक्त शोरूम को तोड़ने का प्रयास किया तो मंत्री ने सीपी को कह कर पुलिस बल देने से रोक दिया। जबकि मंत्री खेमे के लोग उल्टे प्रशासक पर ही आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मोटे पैसे डकार कर एलाइनमेंट बदलवाई थी। सच्चाई चाहे कुछ भी हो जनता के हकूक पर कुठाराघात करते हुए उन से ग्रीन बेल्ट व रोज़ गार्डन छीन लिया गया है। दुख की बात तो यह है कि सेक्टर वासियों के हितैषी होने व उनके अधिकारों की रक्षा करने का दावा करने वाली किसी भी आर डब्लूए ने चूं तक नहीं की। करें भी कैसे, उन्हें राजनेताओं व अफ़सरों की चापलूसी के सिवाय और आता ही क्या है।

एक सप्ताह में वापस लौटे एसडीएम चहल, 'कमाई' ऐसे ही भला कैसे छोड़ दें

फ़रीदाबाद (म.मो.) सोमवार 20 सितम्बर को स्थानीय एसडीएम परमजीत चहल ने अपना रिलीविंग टाइप तो करवा दिया था परन्तु उसे अपने दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें अपनी जुगाड़बाज़ी की कला पर पूरा भरोसा था। इसी जुगाड़बाज़ी के द्वारा इन्होंने अपना तबादला आदेश रद्द करवा कर शुक्रवार को पुन: चार्ज सम्भाल लिया।

करीब एक वर्ष पूर्व वे एसडीएम हिसार के पद पर तैनात थे। लेकिन वहां फ़रीदाबाद जितनी कमाई नहीं थी। इसलिये उन्होंने यहां के कुछ लोगों को पटा कर स्थानीय विधायक नरेन्द्र गुप्ता तक अपनी पहुंच बनाई जिसके द्वारा वे फ़रीदाबाद में 'हूडा' के सम्पदा अधिकारी हो गये। यहां कुछ माह अच्छी-खासी लूट कमाई करते समय उनको महसूस हुआ कि एसडीएम की कमाई कहीं ज्यादा हो रही है। इसलिये चहल ने मुख्यमंत्री खट्टर के राजनीतिक 'सलाहकार' अजय गौड़ की भेंट पूजा करके एसडीएम पद हथिया लिया।

यह पद तो हथिया लिया लेकिन यहां के तमाम राजनेताओं को चहल संतुष्ट न कर पाये, बेशक वे परिवहनमंत्री मूलचंद से लेकर केन्द्रीयमंत्री कृष्णपाल तक खूब चक्कर लगाते रहे। इन नेताओं की नाराजगी को लेकर बीते सप्ताह उनका तबादला स्थानीय स्वशासन विभाग पलवल में हो गया।

जाहिर है कि एसडीएम फ़रीदाबाद के मुकाबले वहां भूखों मरने जैसी स्थिति हो जाती। लिहाज़ा चहल ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिये, लेकिन जब कहीं बात न बनी तो उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की शरण में जाकर दंडवत हो गए, भेंट पूजा तो होती ही है।

यह जुगाड़ काम आया और उन्होंने फ़िर से एसडीएम की कुर्सी हथिया ली। जाहिर है कि अब यहां बैठकर चौके-छक्के लगाकर खट्टर के भ्रष्टाचार मुक्त जुमले को सार्थक कर देंगे।